

500 lok adalats to be held during 2012-13



Justice SK Mittal of the Punjab and Haryana High Court addresses a legal convention. In Rewari, Photo by writer

NAWAL, KSHIRE RASTOGI

REWARI, March-19

District and Sessions Judge Satish Kumar Mittal, along with other functionaries of the district judiciary as well as members of the Bar Association, participated in a convention held for the dissemination of information regarding legal services at the state at the Judicial Complex here recently.

Addressing the convention, Justice Satish Kumar Mittal of the Punjab and Haryana High Court and executive

president of the State Legal Services (SLSA) highlighted the importance of lok adalats, which were a potential channel for the provision of cheap justice while stating that speedy settlement of cases through mutual consent always lead to preservation of money and time of aggrieved parties.

Simultaneously, he made it known that as many as 500 lok adalats would be held throughout the state during 2012-13.

Further stating that while 33,160 cases pertaining to

public utility services like health, water, power, HUDA, banking, transport and postal services were received in the five district level permanent Lok Adalats during the past over five years, 16,865 of them had already been disposed of.

He also said such public utility services courts would now be set up in Rewari, Bhiwani, Karnal, Sonapat and Sirsa districts as well.

Justice LN Mittal of the Punjab and Haryana High Court was also present on the occasion.

गरीब लोगों की मदद करें वकील : जस्टिस मित्तल

जस्टिस ने फतेहाबाद में वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र, रविश्वर में वकीलों के बीच और टोहला में अग्रिमवाद केंद्र का उद्घाटन किया



Justice SK Mittal of the Punjab and Haryana High Court addresses a legal convention. In Rewari, Photo by writer

NAWAL, KSHIRE RASTOGI

REWARI, March-19

District and Sessions Judge Satish Kumar Mittal, along with other functionaries of the district judiciary as well as members of the Bar Association, participated in a convention held for the dissemination of information regarding legal services at the state at the Judicial Complex here recently.

Addressing the convention, Justice Satish Kumar Mittal of the Punjab and Haryana High Court and executive

Legal awareness camps in Kaithal

Our Correspondent

Kaithal, February 9

The District Legal Services Authority (DLSA), Kaithal, is organising legal awareness camps in various villages of Kaithal district to create awareness among the rural people regarding various government schemes and how to get free legal aid under the Legal Services Authority Act from the DLSA.

District and Sessions Judge DS Sheoran, who is also the chairman of the DLSA, and Rajesh Garg, Chief Judicial Magistrate-cum-secretary, DLSA, flagged off the hi-tech legal awareness mobile van on February 2, which was equipped with LCD screen and audio visual system.

The District and Sessions Judge said trained advocates and paralegal volunteers were visiting various villages and addressing the people as per the schedule

fixed by the DLSA. The CIM said a front office had been opened in the Judicial Complex, Kaithal, where panel advocates gave free legal advice on helpline number 01746-235759 during the court hours.

Arvind Khurania, an advocate, said the legal aid team addressed the people in Jagdishpura village where rural women took a keen interest in the camp.

In Dumsara village, the panel advocates found that the ratio of girls was less and women confined themselves to the four walls of their houses. After listening to the welfare schemes and their rights, the people were surprised to know that such facilities and schemes also existed.

In Dewal village, women said they had come out for the first time to listen to the programme as male members of the village do not like their presence in public.

राष्ट्रीय महिला दिवस पर पढ़ाया कानून का पाठ

प्रतिकरण के प्रावधानों का किया उल्लेख, जिलेभर में हुए अनेक कार्यक्रम



राष्ट्रीय महिला दिवस पर छात्राओं को संबोधित करते हुए जज नैन द कानूनी जानकारी देते हुए श्री जे.एम. राधेश्वर गौरी व उपस्थिति।

के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रावधानों का विस्तार से निम्नलिखित, जहाँ विधिक सेवाएं प्रतिकरण के विना समन्वित आर्थिक सुव्यवस्था में प्रतिकरण द्वारा आयोजित की जा रही प्राचीन लोक अदालतों में महिलाओं को होने वाले न्यायिक की भी चर्चा की। जिला संरक्षण अधिकारी सुनीता शर्मा ने जेल विद्या में बाल विवाह विरोधक अधिनियम की जानकारी दी। पंडित कल्याणदास विद्यालय की सेवायुक्त प्राचार्या विद्या कल्याण ने कहा कि देशक देश की नारी ने विभिन्न क्षेत्रों में अपूर्वगुण

का वास होता है और वहाँ नारी का आग्रह और विस्तार होता है, वहाँ असुरों का वास होता है। उनमें विचार जीवन सिंह नैन ने राजकाय कल्याण माध्यमिक विद्यालय वीका में राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संस्था पर व्याख्यान किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अवसर नहीं सफल बनने की जरूरत है। आज महिलाओं का आने अधिकारी के प्रति जागरूक होना सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस अवसर पर स्टाफ के सभी सदस्य भी मौजूद थे।

महिला दिवस पर दी कानून का पाठ

देश का पांचवां आदमी कानूनी

रेवाड़ी, (शशि सैनी) : पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सतीश कुमार मित्तल की अध्यक्षता में न्यायिक परिसर में कानूनी सेवाओं की जानकारी दी गई। तत्पश्चात न्यायाधीशों का लोक सभा के आ निपटारा शीघ्र हो व समय दोनों प्राधिकरण के सौजन्य से अग्रणीय मित्तल ने कहा कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में लघु प्रदेश भर में 500 सचिवलय में महिलाओं के लिए जाएंगी, ताकि जलाना शक्ति एवं महिला का निपटारा कि न्यायिक भविष्य एवं विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव राजेश गौरी ने बताया कि महिला दिवस एवं महिलाओं की शुरुआत की जा सकती है। लोक की 120 करोड़ों का अल्प नृपति को छत्र देने देश में हर 5वां एकला आंचल सराक हो रहा है। में आ जाता है। समय, काल और बचने की सोच को वर्ष 1600 मई ई

अलग रह संरक्षण कार्यालयों के सच-सच विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 की विस्तार से जानकारी देते हुए महिलाओं ज्यदा लंबे को इस संदर्भ में जागरूक करने का कार्य किया। जिला विधिक एवं न्यायिक अधिकारी जिला कोष ने कहा कि पंचायत राज एक्ट के निपटारे में हर महिलाओं को दिए गए 33 प्रतिशत प्राधिकरण बरस कानून में नारी सशक्तिकरण

राष्ट्रीय महिला दिवस पर छात्राओं को संबोधित करते हुए जज नैन द कानूनी जानकारी देते हुए श्री जे.एम. राधेश्वर गौरी व उपस्थिति।

के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रावधानों का विस्तार से निम्नलिखित, जहाँ विधिक सेवाएं प्रतिकरण के विना समन्वित आर्थिक सुव्यवस्था में प्रतिकरण द्वारा आयोजित की जा रही प्राचीन लोक अदालतों में महिलाओं को होने वाले न्यायिक की भी चर्चा की। जिला संरक्षण अधिकारी सुनीता शर्मा ने जेल विद्या में बाल विवाह विरोधक अधिनियम की जानकारी दी। पंडित कल्याणदास विद्यालय की सेवायुक्त प्राचार्या विद्या कल्याण ने कहा कि देशक देश की नारी ने विभिन्न क्षेत्रों में अपूर्वगुण

का वास होता है और वहाँ नारी का आग्रह और विस्तार होता है, वहाँ असुरों का वास होता है। उनमें विचार जीवन सिंह नैन ने राजकाय कल्याण माध्यमिक विद्यालय वीका में राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संस्था पर व्याख्यान किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अवसर नहीं सफल बनने की जरूरत है। आज महिलाओं का आने अधिकारी के प्रति जागरूक होना सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस अवसर पर स्टाफ के सभी सदस्य भी मौजूद थे।

राष्ट्रीय महिला दिवस पर छात्राओं को संबोधित करते हुए जज नैन द कानूनी जानकारी देते हुए श्री जे.एम. राधेश्वर गौरी व उपस्थिति।

महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन

सशक्त हो रहा अबला का आंचल

केथला, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सौजन्य से अग्रणीय मित्तल ने कहा कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में लघु प्रदेश भर में 500 सचिवलय में महिलाओं के लिए जाएंगी, ताकि जलाना शक्ति एवं महिला का निपटारा कि न्यायिक भविष्य एवं विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव राजेश गौरी ने बताया कि महिला दिवस एवं महिलाओं की शुरुआत की जा सकती है। लोक की 120 करोड़ों का अल्प नृपति को छत्र देने देश में हर 5वां एकला आंचल सराक हो रहा है। में आ जाता है। समय, काल और बचने की सोच को वर्ष 1600 मई ई



काकूम में उपस्थित महिलाएं।

भूमिका से बदलों के निशान छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि आज की महिलाएं अपने परम्परागत कर्षों के अलावा पुरुषों के कार्यक्षेत्र में भी



आज समाज

अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही हैं। गौरी ने कहा कि आज के परिवेश में महिलाओं का देश में एक ऐसा वर्ग भी है, जो कानून में उनके



अधिकारों के लिए दूर प्रावधानों से व्यक्ति नहीं है। उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट, दहेज निरोधक अधिनियम 1961, फैमिली कोर्ट एक्ट 1994, बाल विवाह रोधक एक्ट 1929, कामकाजी महिलाओं से होने वाले यौन शोषण, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 तथा पारिवारिक संबंध पुरुषों व महिलाओं की बचत हितकारी, सभी आयोग एक्ट 1987 तथा 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 की विस्तार से जानकारी दी।



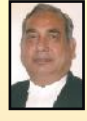
Newsletter



Issue March, 2012



Patron-in-Chief
Hon'ble Mr. Justice Ranjan Gogoi
Chief Justice, High Court, Punjab & Haryana



Executive Chairman
Hon'ble Mr. Justice Satish Kumar Mittal
Judge, High Court, Punjab & Haryana

Member Secretary
Deepak Gupta



Foundation Stone of District Alternative Dispute Resolution (ADR) Center laid by Hon'ble Mr. Justice Satish Kumar Mittal, Executive Chairman, HALSA at Fatehabad

HARYANA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

SCO No. 142 143, First Floor, Sector 34 A, Chandigarh 160 022
Tel.No. : 0172 2604055, Fax No.0172 2622875, Toll Free No.1800 180 2057
Website : www.hslsa.nic.in E mail : hslsa@hry.nic.in, hslsa.haryana@gmail.com

VISIT TO LEGAL AID CLINIC SET UP IN GEETA INSTITUTE OF LAW KARHANS (SAMALKHA) ON 25.2.2012



Hon'ble Mr. Justice S.K.Mittal, Judge, Punjab and Haryana High Court and Executive Chairman, Haryana State Legal Services Authority visited Legal Aid Clinic set up in Geeta Institute of Law, Karhans, G.T.Road, Samalkha (Panipat) on 25.2.2012 in the presence of Mr. S.P.Bansal, Chairman, Mr. Nishant Bansal, Vice-Chairman and Mr. Subhash Mittal, Director Principal of Geeta Institute of

Law. Mr. K.C.Sharma, District and Sessions Judge-cum-Chairman, DLSA, Panipat, Sh. Deepak Gupta, Member Secretary, HALSA also accompanied His Lordship.

MEETING WITH EMpaneLED ADVOCATES AND PARA LEGAL VOLUNTEER AT DISTRICT COURTS COMPLEX, REWARI ON 17.3.2012

Hon'ble Mr. Justice Satish Kumar Mittal, Judge, Punjab and Haryana High Court and Executive Chairman, Haryana State Legal Services Authority held a meeting of Empanelled Advocates and Para Legal Volunteers of District Legal Services Authority, Rewari in the District Courts Complex, Rewari on 17.3.2012 at 11:00 AM in the presence of Hon'ble Mr. Justice L.N.Mittal, Judge, Punjab and Haryana High Court-cum-Administrative Judge, Sessions Division, Rewari, Smt. Sneha Prashar, District and Sessions Judge-cum-Chairman, DLSA, Rewari, Sh. Deepak Gupta, Member Secretary, HALSA and Sh. Rajesh Kumar Bhankar, Chief Judicial Magistrate-cum-Secretary, DLSA, Rewari.



Sh. Deepak Gupta, Member Secretary, Haryana State Legal Services Authority welcomed the dignitaries.

His Lordship heard the Grievances put forth by the Legal Aid Counsels and Para Legal Volunteers, who also shared their experiences and made suggestions for improvement.

Addressing the Legal Aid Counsels and Para Legal Volunteers, His Lordship told them about the objectives of Para Legal Volunteers scheme, Legal Aid Clinics set



up in various villages and about Free and Competent Legal Services. It was told that Para Legal Volunteers are expected to act as a bridge between the common people and legal services institutions. His Lordship exhorted the Para Legal Volunteers to remove the various barriers of Access to Justice for the common man so as to fulfill the objective of the scheme, by identifying the problems of people and help them. They were also told that they

can help the illiterate people for getting various benefits under the Government schemes by drafting their applications and filing up their forms such as ration card/B.P.L./MGNREGA/Old Age Pension, Widow pension, handicap pension etc.

Panel Advocates were exhorted to provide their services in such a manner that the eligible persons do not feel disillusioned. They were told to keep regular communication with them.

After the meeting, his Lordship also addressed media and told them about various activities being carried out by Haryana State Legal Services Authority/ District Legal Services Authorities and that Alternative Dispute Resolution (ADR) Centers are being set up in all Judicial Districts of Haryana, wherein all facilities like Mediation, Lok Adalat, Conciliation etc. shall be provided under one roof.



LAYING OF FOUNDATION STONE OF HARYANA'S DISTRICT ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) CENTER AT FATEHABAD ON 24.3.2012.



Hon'ble Mr. Justice S.K.Mittal, Judge, Punjab and Haryana High Court and Executive Chairman, HALSA laid the Foundation Stone of District Alternative Dispute Resolution (ADR) Centre at Judicial Courts

Complex, Fatehabad on 24.3.2012 in the gracious presence of Hon’ble Mr. Justice K.Kannan, Judge, Punjab and Haryana High Court and Administrative Judge, of Fatehabad Sessions Division, Sh. Deepak Gupta, Member Secretary, Haryana State Legal Services Authority; Sh. L.N.Jindal, Additional District and Sessions Judge-cum-Chairman, District Legal Services Authority, Fatehabad; Sh.M.L.Kaushik, Deputy Commission, Fatehabad; Sh. Satinder Kumar Gupta, Superintendent of Police, Fatehabad; Judicial Officers, Members of Bar Associations; Panel Advocates and Para-Legal Volunteers of District Fatehabad were also present at the occasion.



Earlier Sh. L.N.Jindal, Additional District and Sessions Judge-cum-Chairman, District Legal Services Authority, Fatehabad welcomed Hon’ble Justice Mittal, Justice K.Kannan and other dignitaries.

Hon’ble Mr. Justice S.K.Mittal, Judge, Punjab and Haryana High Court-cum-Executive Chairman, HALSA elaborated in detail activities of HALSA, scheme of Para Legal Volunteers, Legal Aid Clinics etc.

Hon’ble Mr. Justice K.Kannan enlightened the gathering by expressing his esteemed views. He also told at length about the importance and necessity of ADR Center.

STATISTICAL INFORMATION

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF THE ACTIVITIES UNDERTAKEN BY HARYANA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY (W.E.F. 1.2.2012 TO 29.2. 2012)

STATEMENT REGARDING CASES TAKEN UP AND DISPOSED IN LOK ADALATS

Month	No. of Cases taken up	No. of Cases disposed of	Total amount Awarded
February	9,828	3,418	3,94,39,000-00

NO. OF SEMINARS AND CAMPS HELD

Month	No. of Seminar of held	No. of Beneficiaries
February	216	12,882

NO. OF LEGAL AID BENEFICIARIES IN THE STATE OF HARYANA

Month	SC	BC	Women	Children	Custody	Gen.	Total Legal Aid Benefiaries
February	7	Nil	79	2	235	60	383

NO. OF CASES DISPOSED IN THE PERMANENT LOK ADALAT (PUBLIC UTILITY SERVICES)

Month	Transport Services	Postal Telegraph or Telephone Services	Supply of Power; Light or Water	Public Conversancy or sanitation	Services in Hospitals Dispensaries
February	7	93	9	7	Nil

Insurance	Banking, Housing & Finance	Total Cases Settled
10	83	209

MEDIATION TRAINING PROGRAMME

Haryana State Legal Services Authority organized 40 hours Mediation Training Programme in two phases from 16th to 18th March, 2012 and 23rd to 25th March, 2012 at Chandigarh Judicial Academy, Chandigarh. First phase training programme was inaugurated by Hon'ble Mr. Justice Satish Kumar Mittal, Judge, Punjab and Haryana High Court-cum-Executive Chairman, HALSA.

While inaugurating the Session, Hon’ble Mr. Justice Satish Kumar Mittal, Judge, Punjab and Haryana High Court-cum-Executive Chairman of Haryana State Legal



Services Authority stressed that to expedite the disposal of cases, some special enactments have been brought in like the Arbitration & Conciliation Act, 1996; some amendments have been carried out in the existing laws, for instance amendments in the Legal Services Authorities Act, or the insertion of

Section 89 in the Code of Civil Procedure, 1908; and some administrative measures have also been taken in this behalf. But one of the main cause for delay in disposal of the cases is the increase in the institution of cases. Though increase in the institution of case is a healthy sign of a vibrant system meant for democracy in as much as more and more people are becoming aware of legal rights of the common man and go to the Courts for enforcement of their rights or for redressal of their grievances - be it against the State, society or an individual, but at the same time we should find out ways and means for resolution of disputes as quick as possible.

His Lordship also stressed that as the alternative dispute resolution is being developed as complementary means to the judicial process, so need of time is to train judicial officers and advocates objectively on the alternative dispute resolution techniques. With this object in view, the HALSA has organized this training programme on the Art of Mediation and Conciliation.

Earlier Sh. Deepak Gupta, Member Secretary, Haryana State Legal Services Authority welcomed the dignitaries.

Six Advocates Shri Satyawan Ahlawat, Shri Amit Bhatia, Ms. Shalanderf Kaur, Ms. Taranpreet Kaur, Ms. Kanchan Bala, Shri Sanjeev Gupta, Panchkula, Six Advocates Shri Roshan Lal Aggarwal, Shri Baldev Singh, Shri Tarun Mehta, Shri Shiv Kumar Markandey, Ms. Alka Sharda, Ms. Rekha Ahlawat, Ambala, Six Advocates Shri Arvind Kumar Khurania, Shri Vijay Kumar Sharma, Shri Suraj Bhan Panchal, Shri Balbir Bansal, Ms. Sheela Chahal, Ms. Shashi Rana, Kaithal, Six Advocates Mr. Vikram Yadav, Mr. Gaurav Sharma, Mr. Lalit Kumar Mehra, Mr. Mukesh Kaliramana, Ms. Balbir Kaur Gandhi, Ms. Mamta Banga, Sirsa and one Advocate Ms. Rashmi Bhushan, Gurgaon were imparted 40 hours mediation training in two phases by Sh. Prasad Subbanna and Sh. Bharat Kumar Mehta, Trainer, Bangalore Mediation Centre and Sh. Ajay Mehta, and Ms. Nagina Jain, Trainer, Delhi Mediation Centre deputed by Mediation and Conciliation Project Committee, Supreme Court of India.

On the concluding day of the training session, Hon'ble Mr. Justice S.K.Mittal, Judge, Punjab and Haryana High Court-cum-Executive Chairman, HALSA and Hon'ble Mr. Justice Mahesh Grover, Judge, Punjab and Haryana High Court delivered the valedictory speech. His Lordship said that the concept of mediation and conciliation came from the United States of America which is a modern concept for resolving the disputes between the parties through mediation and conciliation. His Lordship pointed out that a conciliator or mediator should promote the mediation between the parties.

His Lordship also pointed out that Counselling cannot achieve miracles, as it can only facilitate. It can open up the individual, give her a self-confidence, it can make her feel less lonely and believe she has someone to reach to. It is preliminary and necessary exercise that would reveal deeper issues and give a lead to other types of Counselling and remedial action or legal rights. By itself it is not complete. Its greatest contribution would be preventive-preventive of drastic action like suicide or mental breakdown; of awareness raising and education; of allowing from being taken unawares or cheated.

Certificates regarding completion of 40 hours Mediation Training Course were awarded to the Advocates by Hon'ble Mr. Justice S.K.Mittal, Judge, Punjab and Haryana High Court-cum-Executive Chairman, HALSA and Hon'ble Mr. Justice Mahesh Grover, Judge, Punjab and Haryana High Court on the concluding session held on 25th March, 2012.



ic Information Campaign of Government of India in H i, District H



Identifying the Unorganized Workers within jurisdiction of DLSA, Bhiwani



National Plan Action 2011 2012 Legal Literacy and Awareness Class for woman at Sirsa

